

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2489  
13.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि संबंधी स्कीम की प्रगति

2489 श्री लहर सिंह सिरिया:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल वित्तीय परिव्यय तथा अब तक स्वीकृत 29 परियोजनाओं की जानकारी सहित भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि संबंधी स्कीम के चरण-॥ के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति क्या है;

(ख) संस्वीकृत परियोजनाओं, जिसमें उत्कृष्टता केंद्र, सामान्य अभियांत्रिकी सुविधा केंद्र, परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र, उद्योग त्वरक और क्वालिफिकेशन पैक संबंधी पहले शामिल हैं, का राज्य-वार विवरण क्या है;

(ग) अब तक संस्वीकृत की गई कितनी परियोजनाएं पूर्ण और संचालनात्मक हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने रोजगार सृजन और भारत के पूंजीगत वस्तु विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के संदर्भ में कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम- चरण-॥ का कुल वित्तीय परिव्यय 975 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन के साथ 1207 करोड़ रुपए है। अब तक 891.37 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 714.64 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन वाली कुल 29 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण निम्नानुसार है:

उत्कृष्टता केंद्र :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य
1.	आईआईटी, रुड़की द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना	उत्तराखंड
2.	आईआईटी, दिल्ली में उत्कृष्टता केन्द्र का विस्तार	दिल्ली
3.	आईआईएस, बेंगलुरु द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र का विस्तार	कर्णाटक
4.	एआरएआई, पुणे में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना	महाराष्ट्र
5.	आईआईटी बीएचयू, वाराणसी द्वारा उत्कृष्टता केन्द्र (सीओई) की स्थापना	उत्तर प्रदेश
6.	सी'टार्क कोयंबटूर में उत्कृष्टता केन्द्र का विस्तार	तमिलनाडु
7.	एएमटीडीसी, आईआईटी मद्रास द्वारा मौजूदा उत्कृष्टता केन्द्र का विस्तार	तमिलनाडु

साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य
1.	स्मार्ट फैक्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएस), बेंगलुरु में सीईएफसी का विस्तार	कर्णाटक
2.	C4i4 द्वारा कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर का विस्तार	परियोजना का मुख्य केंद्र पुणे (महाराष्ट्र) और एक अनुभव केंद्र विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
3.	एआरएआई, पुणे में सीईएफसी की स्थापना	महाराष्ट्र
4.	बीएचईएल, त्रिची में सीईएफसी की स्थापना	तमिलनाडु

परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य
1.	एआरएआई में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधा केंद्रों का विस्तार	महाराष्ट्र
2.	सीएमटीआई, बेंगलुरु में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र का विस्तार	कर्णाटक
3.	बीएचईएल में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधा केंद्र का विस्तार	मध्य प्रदेश /तेलंगाना
4.	(आईएचटी), लुधियाना में मौजूदा परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधा केंद्र का विस्तार	पंजाब
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ़ मशीन टूल्स टेक्नोलॉजी (आईएमटीटी), बटाला में परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधा केंद्र का विस्तार	
6.	फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालक्काड में परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधा केंद्र का विस्तार	केरल

उद्योग त्वरक:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य
1.	एआरटीपीएआरके (आईआईएस), बेंगलुरु द्वारा उद्योग त्वरक (सीएएमआरएस) की स्थापना	कर्णाटक
2.	(एफएसआईडी), (आईआईएस), बेंगलुरु द्वारा उद्योग त्वरक (एसएमआरआईडीएचआई) की स्थापना	
3.	सीएमटीआई द्वारा उद्योग त्वरक की स्थापना	कर्णाटक
4.	एआरएआई, पुणे में उद्योग त्वरक की स्थापना	महाराष्ट्र
5.	आईआईटी, मद्रास द्वारा उद्योग त्वरक की स्थापना	तमिलनाडु
6.	शास्त्र यूनिवर्सिटी, तंजावुर द्वारा उद्योग त्वरक की स्थापना	

7.	पीएसजी कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर द्वारा उद्योग त्वरक की स्थापना	
8.	इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस द्वारा उद्योग त्वरक की स्थापना	तेलंगाना
9.	आईआईटी, रुड़की में उद्योग त्वरक	उत्तराखंड

अर्हता पैकेज:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य
1.	ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एएसडीसी द्वारा 23 अर्हता पैकजों का विकास	दिल्ली
2.	(सीजीएससी), दिल्ली द्वारा 23 अर्हता पैकजों का विकास	
3.	इंस्ट्रुमेंटेशन, ऑटोमेशन, सर्विलांस और कम्युनिकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल (आईएससी एसएससी) द्वारा कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए अर्हता पैकेज का सृजन	

**(घ) और (ङ):** प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने तथा पूंजीगत वस्तु क्षेत्र (में विनिर्माण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम चरण-॥ कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना समीक्षा एवं निगरानी समिति (पीआरएमसी) का गठन किया गया है, ताकि परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

\*\*\*\*\*